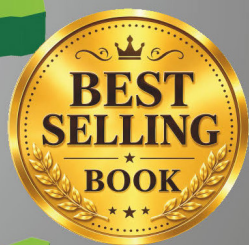


द पावर ऑफ

ट्रियर-III एंड ट्रियर-IV

सिटीज़ ऑफ इंडिया

गेटवे टू \$10 ट्रिलियन इकोनॉमी



सरबजीत एस पुरी
कुणाल अवस्थी



भारत के टियर-III और टियर-IV शहरों की शक्ति

दस ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार

सरबजीत एस पुरी
कुणाल अवस्थी



Natraj
PUBLISHING HOUSE

© सरबजीत एस पुरी, कुणाल अवस्थी

आईएसबीएन (ISBN): 978-81-992238-2-0

संस्करण: 2026

इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या मैकेनिकल, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या कोई भी सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली शामिल है, पुनरुत्पादित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

ISBN: 978-81-687957-7-8



भारत की शक्ति

टियर 2, 3 और 4 कस्बों में विकास के द्वार खोलना



विक्रम लूथरा

चुकदे स्पाइसेस (Chukde Spices) और

यूनिक फ्रैग्रेंसिस (Unique Fragrances) के सह-संस्थापक

आज भारत दो समानांतर वास्तविकताओं के रूप में मौजूद है: महानगरों में रहने वाला शहरी, अंग्रेजी बोलने वाला “इंडिया” और टियर 2, 3 और 4 कस्बों में पनपने वाला विशाल, विविध “भारत”। जहाँ “इंडिया” समृद्धि और आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं यह आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से का हिस्सा है। 80% से अधिक भारतीय “भारत” में रहते हैं, जहाँ आय भले ही मामूली हो सकती है, लेकिन आकांक्षाएँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।

इस क्षेत्र में असीम अप्रयुक्त क्षमता है। जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुंच, मोबाइल का उपयोग और सूचना तक पहुंच बढ़ रही है, वैसे-वैसे बेहतर उत्पादों, सेवाओं और अनुभवों की मांग भी बढ़ रही है। जो व्यवसाय मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, संचार और वितरण में इन बाजारों की अनूठी जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, वे विकास के एक बड़े इंजन को अनलॉक करेंगे।

हालाँकि, असली गेम-चेंजर (बदलाव लाने वाला) सप्लाय चैन (आपूर्ति श्रृंखला) होगी। जो कंपनियाँ भारत के सुदूर इलाकों तक पहुँचने के लिए मजबूत, लागत प्रभावी और स्केलेबल (विस्तार योग्य) सप्लाय चैन बनाने में निवेश करेंगी, वे ही भारत की विकास गाथा के अगले चरण का नेतृत्व करेंगी। ब्रांड्स के लिए अब केवल शीर्ष शहरों की सेवा करना ही पर्याप्त नहीं है; दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले ब्रांड्स के लिए भविष्य “भारत” में निहित है जहाँ वॉल्यूम, वफादारी और अवसर एक साथ मिलते हैं। भारत में जीतने का मतलब वास्तविक भारत के लिए निर्माण करना है जो समावेशी है, जड़ों से जुड़ा है और बढ़ने के लिए तैयार है।



फिरोज़ एच नरकवी

डायरेक्टर जनरल (Director General)

फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैनुफैक्चरर्स - एफएसएनएम (FSNM)

चूंकि मैं भारतीय मिठाई और स्नेक्स उद्योग तथा आइसक्रीम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए इन क्षेत्रों में आइसक्रीम पार्लरों की स्थापना इन समुदायों के भीतर आनंद और फुरसत के पलों की बढ़ती मांग को दर्शाती है। परिवार और दोस्त अब एक साथ इकट्ठा होने और व्यंजनों का आनंद लेने में सक्षम हैं, जो समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। इसी तरह, मिठाई के शोरूम फल-फूल रहे हैं, जो पारंपरिक प्राथमिकताओं और समकालीन दोनों स्वादों को पूरा करते हैं। यह दर्शाता है कि क्रय शक्ति हमेशा से वहां थी; ये शहर गुणवत्तापूर्ण उत्पादों पर खर्च के माध्यम से इसे व्यक्त करने के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

जैसे-जैसे अधिक व्यवसाय इन टियर 3 और टियर 4 शहरों की क्षमता को पहचानेंगे और उनके विकास में निवेश करेंगे, उपभोक्ता खर्च का परिदृश्य विकसित होता रहेगा। यह बदलाव एक व्यापक प्रवृत्ति का संकेत है, जहां बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच एक अधिक जीवंत बाजार की ओर ले जाती है, जो अंततः निवासियों के जीवन को समृद्ध करती है और इन क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देती है।

निष्कर्षतः, भारत में टियर 3 और टियर 4 शहरों पर बढ़ता ध्यान खुदरा परिदृश्य को नया आकार दे रहा है, जिससे इन समुदायों के भीतर सुसंक्रिय शक्ति का पता चलता है। आइसक्रीम पार्लरों और मिठाई शोरूमों का उदय इस रोमांचक विकास का केवल एक पहलू है, जो मिठाई और स्नेक्स क्षेत्र में विकास और नवाचार की क्षमता को उजागर करता है क्योंकि ये शहर अपने नए अवसरों को अपना रहे हैं।



निमल एस कुक

कैपिटल महाराजा ऑर्गनाइजेशन (Capital Maharaja Organization)

के वरिष्ठ बोर्ड सदस्य

निमल कैपिटल महाराजा ऑर्गनाइजेशन के एक वरिष्ठ बोर्ड सदस्य हैं, और साथ ही होल्डिंग कंपनी मैसर्स कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड (M/s Capital Holdings Ltd.) के 4 सदस्यों में से एक हैं। वह पेशे से एक अकाउंटेंट हैं, जिन्हें लगभग 55 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेकिट एंड कोलमैन (Reckitt & Colman) से की थी, और फिर सीलोन टोबैको (Ceylon Tobacco - एक BAT कंपनी) के साथ काम करने के बाद 50 साल पहले CMG में शामिल हो गए। उन्होंने 1977 के सुधारों के समय से श्रीलंका में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को सफलतापूर्वक तैयार और क्रियान्वित किया है। उन्होंने CEB के साथ पहले बिजली खरीद समझौते (Power Purchase Agreement) की शुरुआत की और भारी खनिज रेत के लिए पहला वेट मैग्नेटिक सेपरेटर (wet Magnetic separator) स्थापित किया, साथ ही 1979 में BOT आधार पर प्राइमा मिल (Prima Mill) की पहली BOI परियोजना की शुरुआत की। निमल ने AMCHAM के बोर्ड में काम किया है और श्रीलंका में वित्तपोषण के अवसरों को विकसित करने के लिए OPIC और अमेरिकी निगमों सहित वाशिंगटन की एजेंसियों के साथ काम किया है। उन्होंने अपने करियर के दौरान एशियाई, मध्य पूर्वी और यूरोपीय संघ की एजेंसियों और निगमों के साथ भी काम किया है।

भारत कई संस्कृतियों और कई भाषाओं की एक रहस्यमयी भूमि है। फिर भी इसने हाल के समय में दुनिया को एक सबक देने का काम किया है। भारत अपने लोगों के लाभ के लिए वही करेगा जो उसे करना है, यह ग्लोबल साउथ (Global South) का नेतृत्व एक ऐसे तरीके और शैली में करता है जो ग्लोबल नॉर्थ (Global North) के लिए अज्ञात है, जिसके परिणामस्वरूप रातों-रात वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आया है।

सरबजीत एस पुरी और कुणाल अवस्थी द्वारा लिखित “द पावर ऑफ टियर-III एंड टियर-IV सिटीज ऑफ इंडिया” (The Power of Tier-III and Tier-IV Cities of India) एक समय पर किया गया और व्यावहारिक कार्य है जो ‘भारत’ की सच्ची विकास गाथा को दर्शाता है। यह पुस्तक दृढ़ता से दिखाती है कि मुख्यधारा के आख्यानों में अक्सर अनदेखा किए जाने वाले छोटे शहर और कस्बे किस तरह भारत की \$10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा की कुंजी रखते हैं। अनुसंधान, दूरदृष्टि और जमीनी स्तर के बदलाव की गहरी समझ को मिलाकर, लेखक नीति निर्माताओं, उद्यमियों और उन निवेशकों के लिए एक आवश्यक रोडमैप प्रदान करते हैं जो भारत की भविष्य की समृद्धि के वास्तविक चालकों के साथ जुड़ना चाहते हैं। यह पुस्तक सशक्त रूप से तर्क देती है कि भारत का \$10 ट्रिलियन का सपना महानगरों में नहीं, बल्कि टियर-III और टियर-IV शहरों में अनलॉक होगा। पहुंच, आकांक्षा और अवसर की बाधाओं को तोड़ने वाली डिजिटल क्रांति के साथ, ये उभरते हुए केंद्र भारत की विकास गाथा के वास्तविक इंजन बनने के लिए तैयार हैं।

टियर 3 और टियर 4 शहर भारत माता की कार्यपुस्तिका से प्रेरणा लेंगे और अपनी शैली में अग्रणी बनेंगे।

“टियर-III और IV शहर- जहाँ सपने डिजिटल शक्ति से मिलते हैं।”

“अगला भारत अपने सबसे छोटे शहरों से उदय होगा।”

“आकांक्षा से त्वरण तक: भारत की विकास गाथा यहाँ से शुरू होती है।”



अनिल शर्मा

भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और निर्माता

अनिल शर्मा सिनेमा में चार दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। ‘गदर: एक प्रेम कथा’ और इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले सीक्वल ‘गदर 2’ के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाले, उन्होंने देशभक्ति, भावना और जन-आकर्षण का मिश्रण करने वाली कई प्रतिष्ठित हिट फ़िल्में दी हैं। अपने बैनर ‘अनिल शर्मा प्रोडक्शंस’ के माध्यम से, वह माता-पिता को श्रद्धांजलि देने वाली “वनवास” जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनाना जारी रख रहे हैं, और अब अर्जुन नागा बनाने में व्यस्त हैं, जिससे भारत के सबसे प्रभावशाली कहानीकारों में से एक के रूप में उनकी विरासत और मज़बूत हो रही है।

भारत अपने इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में एक अनोखे आर्थिक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। सालों से, हमारे महानगरों (मेट्रो शहरों) पर ध्यान केंद्रित रहा है जो आकांक्षा, प्रगति और वैश्विक महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। फिर भी, कल की वास्तविक कहानी इन महानगरों से परे, टियर 3 और टियर 4 शहरों में सामने आ रही है जो भारत की जीवंत आत्मा का निर्माण करते हैं। इन्हीं शहरों में बदलाव की अगली लहर गति पकड़ रही है। ये शहर अब “छोटे शहर” नहीं रह गए हैं। वे विकास के उभरते हुए पावरहाउस (शक्ति केंद्र) हैं, जहाँ महत्वाकांक्षा अवसर से मिलती है। वे जीवंत बाज़ार हैं जहाँ उपभोक्ता मांग तेज़ी से बढ़ रही है, प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है, और डिजिटल कनेक्टिविटी भौगोलिक सीमाओं के पार पहुँचने में सक्षम बना रही है। जैसे-जैसे उद्योग विकेंद्रीकृत हो रहे हैं और लागत को युक्तिसंगत बना रहे हैं, विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, खुदरा और लॉजिस्टिक्स में अवसर उन जगहों पर उपजाऊ जमीन पा रहे हैं जिन्हें कभी “छोटे शहर” माना जाता था। सरकारीपहलों, बेहतर बुनियादी ढांचे और एक युवा, महत्वाकांक्षी आबादी के साथ, ये शहर भारत के समावेशी विकास की रीढ़ बनने के लिए तैयार हैं। *‘द पावर ऑफ़ टियर 3 एंड*

टियर 4 सिटीज ऑफ इंडिया: गेटवे टू अ ट्रिलियन-डॉलर इकोनॉमी एक किताब से कहीं बढ़कर एक दृष्टिकोण (विज़न) है। यह इस बात को दर्शाता है कि कैसे लाखों लोगों की आकांक्षाएं, जब प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और अवसर से सशक्त होंगी, तो भारत को अपने अगले विकास पथ पर ले जाएंगी। ट्रिलियन-डॉलर का सपना केवल बोर्डरूम या वित्तीय जिलों में नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इन छोटे कस्बों और शहरों के बाजारों, कार्यशालाओं और उनकी कक्षाओं में गढ़ा जाएगा। मेरा मानना है कि पाठकों को इन पृष्ठों में न केवल तथ्य और विश्लेषण मिलेंगे, बल्कि भारत के भीतरी इलाकों में रहने वाली अपार क्षमता को पहचानने, उसमें निवेश करने और उसके साथ साझेदारी करने की प्रेरणा और आमंत्रण भी मिलेगा। जबकि महानगर फल-फूल रहे हैं, यह नई क्षमता बहु-प्रतीक्षित समावेशी विकास लाएगी। यह पुस्तक नेताओं, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और स्वप्नद्रष्टाओं को स्पष्ट से परे देखने, सामान्य स्थानों में असाधारण क्षमता को पहचानने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करे कि भारत के ट्रिलियन-डॉलर के भाग्य का रास्ता इसके छोटे शहरों के दिल से होकर गुजरता है।



शांता मार्टिन

मर्क ग्रुप (Merc Group) की डायरेक्टर

शांता मार्टिन लॉजिस्टिक्स और सप्लाय चेन लीडरशिप में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक अनुभवी वैश्विक सीईओ हैं। मर्क ग्रुप की डायरेक्टर के रूप में, वह प्रमुख वैश्विक बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान और डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाती हैं। इससे पहले, ईसीयू वर्ल्डवाइड (ECU Worldwide) की रीजनल सीईओ के रूप में, उन्होंने कंपनी के सबसे बड़े और सबसे लाभदायक क्षेत्रों में से एक का प्रबंधन किया, जिसमें दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई और वैश्विक कॉरपोरेट्स के लिए एंड-टू-एंड (शुरुआत से अंत तक) सप्लाय चेन समाधानों का निर्माण किया गया। 'वुमन सीईओ ऑफ द ईयर' और 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर' सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, शांता नेतृत्व में महिलाओं का समर्थन करते हुए लॉजिस्टिक्स के भविष्य को आकार देने वाली एक दूरदर्शी हैं। वह IWLF के सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं और विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए महिला उद्यमियों के लिए एक मंच तैयार कर रही हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और इसके \$10 ट्रिलियन की सीमा तक पहुँचने की उम्मीद है। दुनिया भर के पर्यवेक्षक, जिसमें सिंगापुर भी शामिल है जहाँ मैं स्थित हूँ, सभी जानते हैं कि इसके चालकों में औद्योगिक विकास और डिजिटल उपभोग की आदतें शामिल हैं। ये विशाल महानगरों में केंद्रित हैं। कुणाल और सह-लेखक सरबजीत स्वीकृत आख्यान (accepted narrative) में एक अतिरिक्त परत का प्रस्ताव करते हैं। 'भारत की रीढ़' टियर 3 और टियर 4 शहर हो सकते हैं। ये उद्यमिता और अनुकूल जनसांख्यिकी (favorable demographics) से भरे हुए हैं। लेखक मानचित्रित करते हैं—

—उन अवसरों को जो उनके सीधे अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित हैं। चाहे पाठक

एक व्यवसायी हो, नीति निर्माता हो या शैक्षणिक क्षेत्र से हो, वे निश्चित रूप से प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण और साक्ष्यों से लाभान्वित होंगे।

लेखकों को बधाई, और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं!



फूंग चोंग लेक

एसजीलिस्टकॉस (SGListCos) के सचिवालय प्रमुख

फूंग चोंग लेक उस टीम का नेतृत्व करते हैं जो फैमिली ऑफिसों (Family Offices) के साथ जुड़ती है, जिसका उद्देश्य एक जीवंत सिंगापुर पूंजी बाजार का निर्माण करना है जो फैमिली ऑफिसों की जरूरतों के लिए प्रासंगिक हो। वह फैमिली ऑफिस क्षेत्र को लक्षित करने वाले विशेष कार्यक्रमों पर निजी बैंकों (Private Banks) के साथ भी सहयोग करते हैं। यहाँ के मुख्य विषय परोपकार (Philanthropy), ईएसजी (ESG) और उद्यम विकास (Enterprise Development) हैं।

इसमें एसजीएक्स इक्विटीज (SGX Equities), फिक्स्ड इनकम (Fixed Income), करेंसी (Currency) और कमोडिटी (Commodity) उत्पादों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है जो एसजीएक्स सूचीबद्ध कंपनियों, फैमिली ऑफिसों और निजी बैंकों को लाभ पहुंचा सकते हैं। वह एसजीएक्स कॉर्पोरेट / इन्वेस्टर एक्सेस कैलेंडर का भी प्रबंधन करते हैं।

उनके कार्यक्षेत्र में खनिज, तेल और गैस (“MOG”) क्षेत्र में नई लिस्टिंग की शुरुआत भी शामिल है, जिसमें अन्वेषण (exploration), विकास और उत्पादन शामिल हैं, साथ ही स्थिरता (Sustainability) क्षेत्र, और इससे पहले बायोटेक, मेडटेक और रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी (Navikarniya Urja) क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने पहले सभी क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और सऊदी अरब के बाजारों को कवर किया है।

इसके अतिरिक्त, वह एसजीलिस्टकॉस (SGListCos) के सचिवालय प्रमुख हैं, जो सभी एसजीएक्स सूचीबद्ध कंपनियों का संघ है। एसजीलिस्टकॉस के उद्देश्यों में थॉट लीडरशिप एंड एडवोकेसी (Thought Leadership & Advocacy), ईएसजी (ESG) और कॉर्पोरेट एक्सेस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस (Corporate Access & Investor Relations) शामिल हैं।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रॉक्टर एंड गैम्बल (Procter & Gamble) से की थी जहाँ वे लिक्विड्स टेक्नोलॉजी लीडर (Liquids Technology Leader) थे। उन्होंने आरएचबी प्राइवेट इक्विटी (RHB Private Equity) में सीनियर मैनेजर के रूप में और स्प्रिंगबोर्ड-हार्पर इन्वेस्टमेंट्स (Springboard-Harper Investments - VC) में इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में भी पदों पर कार्य किया है।

उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूएसए (Purdue University, USA) से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइन्स (Bachelor of Science) की डिग्री प्राप्त की है। उनके पास इनसीड (INSEAD), सिंगापुर से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री भी है।



ओसामा जलाली

अनुभवी खाद्य लेखक, शोधकर्ता, सलाहकार और एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ

ओसामा जलाली एक अनुभवी खाद्य लेखक, शोधकर्ता, सलाहकार और एक सेलिब्रिटी मास्टर शेफ हैं। वे क्षेत्रीय भारतीय व्यंजनों को पुनर्जीवित करने के दूत हैं और हमारे देश की समृद्ध पाक विरासत के छिपे हुए पाक रत्नों को प्रदर्शित करने के मिशन पर हैं। उन्होंने दुनिया भर में 2000 से अधिक रेस्तरां की सफलतापूर्वक समीक्षा की है। ओसामा उन कुछ लेखकों में से एक हैं जिन्होंने खुद को केवल लिखने तक सीमित नहीं रखा है बल्कि उन्हें रसोई में काम करना भी बेहद पसंद है। वे दुनिया भर के प्रीमियम होटलों और निजी 'दावतों' के लिए अपनी पत्नी बेगम नाज़िया खान और माँ बेगम नाज़िश जलाली (जिन्हें लोकप्रिय रूप से अम्मी जलाली के नाम से जाना जाता है) के साथ फ्रंटियर, रामपुरी, शाहजहानी, हेरिटेज और लॉस्ट रेसिपी (लुप्त व्यंजन) मेनू तैयार करते हैं। पिछले दशक में उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख होटल श्रृंखलाओं (जैसे ओबेरॉय/ट्राइडेंट/शेरेटन/जेडब्ल्यू मैरियट/लीला/रिट्ज कार्लटन/ले मेरिडियन और कई अन्य) के साथ फूड फेस्टिवल आयोजित किए हैं। उनकी विशेषज्ञता मुगल सम्राटों और नवाबों के पुश्तैनी और भूले-बिसरे व्यंजनों में है। पुरानी दिल्ली की गलियों में जन्मे और पले-बढ़े, उनकी पैतृक जड़ें उत्तर प्रदेश की एक रियासत से जुड़ी हैं जिसे रामपुर कहा जाता है जो अपने अनूठे रामपुरी व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। उनके शोधित विशिष्ट व्यंजनों को 'द मुगल प्लेट' नामक मेनू के तहत तैयार किया गया है। विभिन्न प्रकाशनों में देश के विभिन्न खाद्य लेखकों द्वारा उनके बयानों को उद्धृत किया गया है।

भारत की आर्थिक विकास गाथा अक्सर उसके महानगरों और टियर 1 शहरों के चश्मे से बताई जाती है, लेकिन वास्तविक बदलाव टियर 3 और टियर 4 कस्बों में सामने आ रहा है। कभी बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बहुत छोटा माना जाने वाला यह कस्बा अब बढ़ती आय, आकांक्षी जीवन शैली और बढ़ते संपर्क (कनेक्टिविटी) से प्रेरित होकर जीवंत उपभोग केंद्रों के रूप में उभर

रहा है। इस बदलाव से सबसे अधिक लाभ उठाने वाले क्षेत्रों में, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) और खाद्य एवं पेय (F&B) उद्योग स्पष्ट रूप से सबसे आगे हैं। भारत के टियर 3 और टियर 4 कस्बों में हॉस्पिटैलिटी और एफएंडबी उद्योग इस दशक के सबसे रोमांचक विकास क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ये बाजार मजबूत सांस्कृतिक जड़ों के साथ आधुनिक अनुभवों की भूख का संयोजन करते हैं, जो उद्यमियों और निवेशकों को नवाचार करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे आय, बुनियादी ढांचा और आकांक्षाएं एक साथ मिलेंगी, छोटे शहर न केवल भारत के उपभोग उछाल में भाग लेंगे बल्कि इसका नेतृत्व भी करेंगे।



अरुणकुमार हरदियन

सूरिनाम गणराज्य के राजदूत

भारत की कहानी अक्सर उसके बड़े महानगरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जो वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के केंद्र हैं, के चश्मे से बताई जाती है। फिर भी, मेरे अवलोकन और अनुभव में, भारत की वास्तविक धड़कन इन हलचल भरे वैश्विक केंद्रों से कहीं दूर धड़कती है। यह टियर 3 और टियर 4 कस्बों में है जहाँ कोई भी उस शांत शक्ति, लचीलापन और सरलता को पाता है जो राष्ट्र को बनाए रखती है और आगे बढ़ाती है।

ये कस्बे आकार में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका महत्व गहरा है। ये वे स्थान हैं जहाँ परंपराएँ सुरक्षित हैं, भले ही आधुनिकता की आकांक्षाएँ जड़ें जमा रही हों। वे उन उद्यमियों का पोषण करते हैं जो सीमित संसाधनों के साथ लेकिन असीम दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं। वे शिक्षा और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उत्सुक युवा दिमागों के घर हैं, जो अक्सर रचनात्मक और लीक से हटकर अवसरों का पीछा करने के लिए पारंपरिक बाधाओं को पार कर जाते हैं।

एक राजनयिक के रूप में पूरे भारत में अपनी यात्राओं और बातचीत के दौरान, मैं यह देखकर अभिभूत हुआ हूँ कि कैसे ये कस्बे, जिन्हें कभी मुख्यधारा से दूर माना जाता था, अब विकास के जीवंत इंजनों के रूप में उभर रहे हैं। उनके लोग सादगी और महत्वाकांक्षा का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। उनके सामुदायिक जीवन की गर्मजोशी, विरासत के प्रति उनका सम्मान, और भारत के वैश्विक उदय में भाग लेने की उनकी भूख, सभी एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जहाँ विकास अब कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के विशाल परिदृश्य में साझा किया जाएगा।

टियर 3 और टियर 4 कस्बे केवल विकास की “अगली सीमा” नहीं हैं; वे भारत की समावेशी प्रगति की वास्तविक आत्मा हैं। उनकी क्षमता को पहचानना न्यू इंडिया (नए भारत) की धड़कन को समझना है—एक ऐसा भारत जो न केवल शहरी है, बल्कि अपनी अर्ध-शहरी और ग्रामीण नींव में गहराई से निहित है।

इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं इस विषय की खोज की सराहना करता हूँ। क्योंकि इन कस्बों में कल के सपने छिपे हैं, और उनके उदय में, हम भारत के बदलाव की सबसे प्रामाणिक कहानी को सामने आते देखेंगे।



मनदीप नलवा

टारस वेल्थ एडवाइजर्स (Tarus Wealth Advisors) के संस्थापक और ग्रुप सीईओ

मनदीप नलवा टारस वेल्थ एडवाइजर्स के संस्थापक और ग्रुप सीईओ हैं, जो 2008 में स्थापित एक अग्रणी मल्टी-फैमिली ऑफिस है। आईआईएम अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) के पूर्व छात्र, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉयचे बैंक (Deutsche Bank) से की थी और बाद में एचएसबीसी (HSBC), मेरिल लिंच (Merrill Lynch) और सिटी प्राइवेट बैंक (Citi Private Bank) में वरिष्ठ पदों पर रहे, जहाँ उन्होंने फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर में वेल्थ मैनेजमेंट व्यवसाय का निर्माण किया। 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, मनदीप को प्राइवेट बैंकिंग, क्लाइंट एडवाइजरी और जोखिम प्रबंधन में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उनके नेतृत्व में, टारस ने 35 देशों में USD 3 बिलियन से अधिक की संपत्ति (assets) के प्रबंधन तक विस्तार किया है, जिसकी दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में मजबूत उपस्थिति है।

भारत और मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया में अवसर का मुख्य स्रोत 'मिडिल इंडिया' (मध्य भारत) को बंधनों से मुक्त करना और इसकी आबादी के लिए अवसरों की समानता लाना है, जैसा कि बड़े शहरी केंद्रों के लिए उपलब्ध है। इस तरह का एक पाठ शासन मॉडल (governance models) के लिए बहुत प्रेरक तर्क है जो दूरगामी, समावेशी और व्यापक आधारित हो, जो न केवल मीडिया कवरेज को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित हो बल्कि उन क्षेत्रों पर भी हो जो आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था के प्रेरक साबित होंगे। जैसे-जैसे भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है, यह वैश्विक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा और शेष विश्व के लिए अवसर का इंजन बनेगा क्योंकि यह वर्तमान सदी में 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उससे आगे की ओर बढ़ रहा है। उस माहौल में, निवेशकों के लिए अवसर प्रदर्शित करके और सरकार दोनों के लिए, मैं कुशल अवस्थी और सरबजीत सिंह पुरी को भारत के टियर 3 और टियर 4 कस्बों पर व्यापक-आधारित ध्यान केंद्रित करने की एक अच्छी तरह से शोधित और स्पष्ट रूप से प्रमाणित

आवश्यकता के लिए बधाई देता हूँ।

यह पुस्तक उभरते भारत को लक्षित करने वाले उद्यमी के लिए आर्थिक रणनीति के लिए, सरकार के अधिकारियों के लिए आर्थिक विकास योजनाओं का विवरण देने के लिए, या अवसर के पहियों को थोड़ा तेज़ी से घुमाने के इच्छुक परोपकारियों (philanthropists) के लिए एक आवश्यक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है।



आमोद विजयवर्गीय

पर्ल एकेडमी स्कूल ऑफ बिजनेस (Pearl Academy School of Business) के निदेशक

आमोद पर्ल एकेडमी स्कूल ऑफ बिजनेस के निदेशक हैं। एक कॉर्पोरेट लीडर से अकादमिक पेशेवर बने आमोद के पास कैपजेमिनी (Capgemini), अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young), जेनपैक्ट (Genpact), गोदरेज (Godrej), आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) और हिताची कंसल्टिंग (Hitachi Consulting) जैसे वैश्विक संगठनों के लिए रणनीति, विकास, परिवर्तन और संचालन को चलाने का 28 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। उनके प्रभावशाली पोर्टफोलियो में द कोका-कोला कंपनी (The Coca-Cola Company), डेयरी फार्म (Dairy Farm), एनर्जी ऑस्ट्रेलिया (Energy Australia), बॉम्बार्डियर (Bombardier) और जार्डिन ग्रुप (Jardine Group) जैसे ग्राहकों का प्रबंधन शामिल है, जिन्होंने 100 मिलियन USD से अधिक के सौदे बेचे हैं और 250 million USD से अधिक के पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया है। टियर 3 शहर से आने वाले व्यक्ति के रूप में, मैंने इन उभरते शहरी केंद्रों के अनूठे आकर्षण और क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। वहीं पले-बढ़े होने के कारण, मैंने छोटे शहरों की परिवर्तनकारी शक्ति और उनके लोगों के लचीलेपन को देखा है। यह व्यक्तिगत जुड़ाव ही है जो भारत में टियर 3 और टियर 4 शहरों की शक्ति पर कुणाल अवस्थी की पुस्तक को मेरे दिल के इतना करीब बनाता है। मेरे मित्र कुणाल और मैंने इन शहरों की क्षमता के बारे में कई बातचीत की है, और इस विषय के लिए उनका जुनून उनके लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सावधानीपूर्वक अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से, कुणाल ने इन शहरों की कहानियों को जीवंत किया है, उनकी ताकत, चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डाला है।

यह पुस्तक केवल शहरी विकास के अध्ययन से कहीं अधिक है; यह इन शहरों के भीतर छिपी क्षमता का एक प्रमाण है। कुणाल का काम प्रदर्शित करता है, उस उद्यमशीलता की भावना, नवाचार और समुदाय-संचालित पहलों को जो टियर 3 और टियर 4 शहरों में विकास को गति दे

रहे हैं। कुणाल के दृष्टिकोण में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वह है आशावाद को व्यावहारिकता (pragmatism) के साथ संतुलित करने की उनकी क्षमता। वे इन शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और साथ ही उन अवसरों पर भी प्रकाश डालते हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। उनके विचार नीति निर्माताओं, व्यवसायों और इन उभरते शहरी केंद्रों की विकास क्षमता का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए अमूल्य होंगे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लोगों के जीवन पर इन शहरों के प्रभाव को देखा है, मेरा मानना है कि कुणाल की पुस्तक समान पृष्ठभूमि वाले पाठकों को गहराई से प्रभावित करेगी। उनका काम यह याद दिलाता है कि भारत की विकास गाथा केवल महानगरों के बारे में नहीं है; यह उन छोटे शहरों के बारे में भी है जो नवाचार, उद्यमिता और बदलाव को प्रेरित कर रहे हैं। कुणाल की पुस्तक के लिए यह प्रस्तावना (foreword) लिखते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि यह सार्थक बातचीत और कार्यों को प्रेरित करेगी। टियर 3 और टियर 4 शहरों की क्षमता पर प्रकाश डालने के लिए कुणाल का समर्पण इस क्षेत्र में एक मूल्यवान योगदान है, और मैं उनके काम के प्रभाव को देखने के लिए उत्सुक हूँ।



गंगेश चतुर्वेदी

प्रमुख निर्यात (EP&D), टाटा स्टील लिमिटेड (Tata Steel Limited)

भारत के टियर 3 और टियर 4 शहरों में एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव चल रहा है। उपभोग के पैटर्न (consumption patterns) तेज़ी से बदल रहे हैं, जो उद्योगों को नया आकार दे रहे हैं और अवसरों की नई सीमाओं को खोल रहे हैं।

यह बदलाव कई ताकतों के संयोजन से प्रेरित है: तीव्र शहरीकरण, भविष्योन्मुखी सरकारी पहल और डिजिटलीकरण की निरंतर गति। आज व्यावसायिक लेन-देन अब समय या स्थान के बंधनों से बंधे नहीं हैं; प्रौद्योगिकी ने बाज़ार को हर घर के दरवाज़े तक पहुँचा दिया है, जिससे उद्यमियों और उपभोक्ताओं दोनों को समान रूप से सशक्त बनाया गया है। कुशल, अभिनव व्यावसायिक मॉडल अपनी जगह बना रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में गति बढ़ रही है। ई-कॉमर्स की व्यापक स्वीकार्यता अब एक सामान्य बात है, और जब इसे लागत लाभ और प्रचुर विकास क्षमता के साथ जोड़ा जाता है, तो यह निवेश और विस्तार के लिए एक उपजाऊ ज़मीन तैयार करता है। जैसे-जैसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार जारी है, ये शहर आर्थिक विकास के जीवंत इंजन बनने के लिए तैयार हैं। यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और आगे का रास्ता अभूतपूर्व संभावनाओं का वादा करता है।



डॉ. मुकेश कुमार

केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) के प्रबंध निदेशक

डॉ. मुकेश कुमार 01 नवंबर, 2017 से केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक हैं। उनके कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय भंडार ने एक शानदार प्रतिष्ठा हासिल की है, जिसने 07 वर्षों में 10 गुना वृद्धि दर्ज की है और 2017-18 में ₹750 करोड़ के टर्नओवर से बढ़कर 2024-25 में ₹8000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर लिया है, जो दुनिया भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अभूतपूर्व और अद्वितीय है। डॉ. मुकेश कुमार देश में सहकारी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित पेशेवर हैं। वे ज्ञान की विभिन्न धाराओं के एक उत्साही पाठक और गतिशील छात्र हैं। शैक्षणिक स्तर पर, उनके पास MA, LLB, MBA, PGDCA, B.Ed, DHM&OA, CSMSI जैसी विभिन्न डिग्रियाँ हैं और प्रतिष्ठित सहकारी संगठनों के प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान तथा उनकी असाधारण सेवाओं की मान्यता में, उन्हें भारत और यूएसए के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (Doctor of Business Administration) और डॉक्टर ऑफ लेटर्स (Doctor of Letters) की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025, जब दुनिया इस साल को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (International Year of Cooperatives) के रूप में मना रही है, युवा भारत की क्षमता और समृद्धि एवं मजबूत अर्थव्यवस्था के उसके रोडमैप का पता लगाने का यह मूक कार्य, जो किशोरों, युवाओं और उनके साथ खड़े अमूल्य अनुभव वाले अमीर-बुजुर्गों (rich-agers), श्रमिकों, किसानों, उद्यमियों और भारत में रहने वाले व्यापारिक समुदाय के दिमाग से होकर गुजरता है, वह प्रौद्योगिकी और सशक्तिकरण के उपकरणों के माध्यम से अपनी सफलता की कहानी को अपने तरीके से सहजता से लिख रहा है। गाँवों और कस्बों से व्यापार करने की सहजता आर्थिक विकास में अपनी बड़ी भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार है। टियर-3 और टियर-4 शहर अब युवा पीढ़ी को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ने के लिए विभिन्न अवसर

प्रदान करके मेट्रो शहरों के शून्य (वैक्यूम) को भरने के लिए तैयार हैं, जो आकांक्षाओं, ऊर्जा, समर्पण, प्रतिबद्धता से भरपूर हैं और भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बनाने के लिए अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इस संकलन को सामने लाने का अवसर, जब दुनिया भर में परिस्थितियां और समीकरण काफी चुनौतीपूर्ण हैं, और भारत प्रौद्योगिकी की प्रगति, अपने लोगों के आर्थिक विकास और भारत की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने साहस और ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत सुधारों की अगली पीढ़ी में प्रवेश कर चुका है जिससे लोगों में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो रही है, और यह काफी हद तक कम की गई जीएसटी (GST)/कर संरचना के माध्यम से कीमतों को नीचे लाकर आम लोगों तक लाभ और रियायतें पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जन-हितैषी सुधारों के प्रभाव और परिणाम आम लोगों के जीवन में नाटकीय बदलाव लाएंगे ताकि वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को दिए गए 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' (सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन) के मंत्र को अपनाकर भारत की एक नई कहानी लिख सकें, ताकि देश को ब्रह्मांड में एक महाशक्ति बनाया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक सभी आयु वर्ग के लोगों और रुचि के सभी क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में भारत की सफलता और सहकारी समृद्धि के साथ अपनी खुद की सफलता की कहानी लिखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्दृष्टि और आत्मविश्वास देगी।

प्रस्तावना (Preface)

भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। यह एक ऐसा देश है जहाँ चमचमाते महानगर वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ आसमान छू रहे हैं, भले ही अनगिनत छोटे शहर शांत लेकिन कम दृढ़ तरीकों से परंपराओं, आजीविका और आकांक्षाओं का पोषण करते हैं। बहुत लंबे समय से, भारत के विकास पर चर्चा को इसके टियर I शहरों के चश्मे से ही देखा गया है। मुंबई की आर्थिक जीवंतता, बेंगलुरु की उद्यमशीलता की ऊर्जा, दिल्ली की प्रशासनिक केंद्रीयता और चेन्नई या कोलकाता के सांस्कृतिक आकर्षण ने नीतिगत कल्पना और व्यावसायिक रणनीतियों दोनों पर अपना दबदबा बनाए रखा है। फिर भी, जैसे-जैसे हम इक्कीसवीं सदी में गहराई से बढ़ रहे हैं, एक अलग कहानी सामने आ रही है, जो गगनचुंबी इमारतों या हाई-टेक परिसरों से शुरू नहीं होती है, बल्कि टियर III और टियर IV शहरों की गलियों में आकार लेती है।

यह पुस्तक, 'द पावर ऑफ टियर 3 एंड 4 सिटीज' (The Power of Tier 3 and 4 Cities), इस मान्यता से पैदा हुई थी कि भारत की विकास गाथा इन कस्बों को समझे बिना अधूरी है जो "भारत" की रीढ़ हैं। ये ऐसे शहर हैं जिन्हें अक्सर वैश्विक कल्पना में मामूली, परिधीय (peripheral) या अदृश्य के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन जो वास्तव में उद्यमशीलता के उत्साह, जनसांख्यिकीय ऊर्जा और सांस्कृतिक समृद्धि से भरे हुए हैं। उनके बीच यात्रा करना गतिमान बदलाव को देखना है: पारंपरिक मंडियों के साथ नए मॉल उभर रहे हैं, छात्र ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं में भाग ले रहे हैं जबकि उनके माता-पिता परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों का प्रबंधन करते हैं, सूक्ष्म-उद्यमी व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से उत्पाद बेच रहे हैं जबकि व्यापारी सदियों पुराने बाजारों में मोलभाव कर रहे हैं। यह विरोधाभास कोई अराजकता नहीं है, बल्कि यह भारत के परिवर्तन का वास्तविक चेहरा है।

इस पुस्तक को लिखने की हमारी प्रेरणा इस अनकही वास्तविकता से बार-बार सामना होने से मिली। हमने देखा कि छोटे शहरों में लोगों की आकांक्षाएं अब भूगोल तक सीमित नहीं थीं।

इंटरनेट के प्रसार, मोबाइल नेटवर्क के तेजी से विस्तार और समावेशन के उद्देश्य से चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के कारण, एक जिला मुख्यालय और एक मेट्रो शहर के बीच की दूरी न केवल भौतिक रूप से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सिमट रही है। आज टियर IV शहर के युवा पुरुषों और महिलाओं में एक स्टार्टअप शुरू करने, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में शामिल होने या विदेशों में अध्ययन करने का सपना देखने की उतनी ही संभावना है जितनी कि बड़े शहरों के उनके साथियों में। अंतर केवल उस पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) में है जो उन्हें घेरे हुए है, जो अभी भी विकसित हो रहा है, कभी-कभी असमान रूप से, लेकिन हमेशा आगे बढ़ रहा है। यह वही विकसित होता पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) है जिसे यह पुस्तक मानचित्रित करने का प्रयास करती है। हम टियर III और टियर IV कस्बों को विकास की प्रतीक्षा कर रहे मामूली स्थानों के रूप में नहीं, बल्कि भारत की विकास गाथा को पहले से ही शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण इंजनों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके योगदान को एमएसएमई (MSME) समूहों के विस्तार में, सस्ती निजी शिक्षा के प्रसार में, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं (agricultural value chains) की गतिशीलता में और ई-कॉमर्स को बढ़ते रूप से अपनाने में देखा जा सकता है। ये कस्बे महानगरों द्वारा “बचाए जाने” की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं; वे लचीलेपन, आकांक्षा और नवाचार के केंद्रों के रूप में सक्रिय रूप से खुद को पुनर्जीवित कर रहे हैं।

इस पुस्तक की संरचना इसी दृष्टिकोण को दर्शाती है। भाग एक इन कस्बों, उनकी जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और ढांचागत प्रक्षेपवक्रों (infrastructural trajectories) की एक बुनियादी समझ प्रदान करता है। भाग दो उनकी ताकतों की गहराई में जाता है, जिसमें औद्योगिक क्षमता से लेकर सहकारी आंदोलन और स्वयं सहायता समूहों (self-help groups) का उदय शामिल है। भाग तीन विभिन्न उद्योगों में अवसरों की खोज करता है, यह प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय अब इन बाजारों की अनदेखी करने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकते। भाग चार उन डिजिटल उपभोग पैटर्नों पर प्रकाश डालता है जो दैनिक जीवन, वाणिज्य और शासन को नया आकार दे रहे हैं। अंत में, ये खंड मिलकर एक ऐसा मोजेक (चित्रांकन) बनाते हैं जो एक ही समय में अनुभवजन्य और विचारोत्तेजक, विश्लेषणात्मक और प्रेरणादायक है।

इस पुस्तक को लिखना “विकास” को हम कैसे परिभाषित करते हैं, इस पर फिर से विचार करने का एक अभ्यास भी रहा है। दशकों से, विकास को शहरीकरण और बड़े शहरों के साथ जोड़कर देखा जाता था। लेकिन भारत केवल अपने महानगरों पर ध्यान केंद्रित करके \$10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। छोटे शहरों की लागत के लाभ, उपभोक्ता आधार और सुप्त प्रतिभा पूल (latent talent pools) समावेशी विकास के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। यदि सही नीतियों और निवेशों के साथ इनका पोषण किया जाए, तो ये कस्बे आने वाले दशकों में महानगरों के नेतृत्व वाले विकास के केवल पूरक नहीं होंगे, बल्कि शायद उससे भी आगे निकल

जाएंगे। वे पीछे छूटे हुए (“backward”) स्थान नहीं हैं जो बराबरी करने का इंतज़ार कर रहे हैं; वे भविष्योन्मुखी स्थान हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही अपनी पहचान बना रहे हैं।

यह प्रस्तावना कृतज्ञता का प्रतिबिंब भी है। शोध को संकलित करने, साक्षात्कार आयोजित करने और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने में, हमारा सामना अनगिनत ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो टियर III और टियर IV भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं: वह किसान जो एग्री-टेक (Agri-tech) उपकरणों के साथ प्रयोग करता है, वह युवा छात्र जो मुश्किल परीक्षाओं को पास करता है एक छोटे शहर के कोचिंग सेंटर से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, वह महिला उद्यमी जो रसोई के उद्यम को एक ऑनलाइन ब्रांड में बदल देती है, वह शिक्षक जो ग्रामीण छात्रों तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाता है, और वह व्यापारी जो पारंपरिक नेटवर्क को आधुनिक लॉजिस्टिक्स के साथ मिलाता है। उनका जीवन हमें बताता है कि विकास कोई अमूर्त आँकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है, जो वास्तविक समय में सामने आ रहा है। यह हमारी आशा है कि यह पुस्तक कई प्रकार के पाठकों (दर्शकों) की मदद करेगी। नीति निर्माताओं के लिए, यह समावेशिता के साथ शासन को फिर से तैयार करने का एक निमंत्रण है। व्यावसायिक नेताओं के लिए, यह संतृप्त (saturated) मेट्रो बाजारों से परे देखने और ‘भारत’ में निवेश करने का आह्वान है। शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए, यह विकेंद्रीकृत शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए एक वैचारिक और व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है। नागरिकों के लिए, यह एक याद दिलाता है कि भारत का भविष्य केवल प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों में नहीं बल्कि साधारण सड़कों पर आकार ले रहा है, जहाँ लाखों लोगों की असाधारण क्षमता अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही है।

टियर III और टियर IV कस्बों की यात्रा अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है, लेकिन यह पहले से ही सीखों से समृद्ध है। जैसा कि भारत वैश्विक आर्थिक प्रमुखता के मुहाने पर खड़ा है, ये कस्बे लचीले, आकांक्षी और गहराई से जुड़ों से जुड़े हुए हैं समुदाय में गहराई से जुड़े हुए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास की कहानी केवल आंकड़ों के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में हो। हम इस पुस्तक को उनकी भूमिका की मान्यता और उनके भविष्य के रोडमैप दोनों के रूप में पेश करते हैं।

आभार प्रदर्शन (Vote of Thanks)

जैसे ही हम इस कार्य को पूर्णता की ओर लाते हैं, हम इस बात से गहराई से अवगत हैं कि इस तरह की पुस्तक कभी भी केवल इसके लेखकों की उपलब्धि नहीं होती है। यह व्यक्तियों और संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला के सामूहिक अंतर्दृष्टि, प्रोत्साहन और योगदान का परिणाम है। इसलिए, उन सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य और विशेषाधिकार दोनों है जिन्होंने 'द पावर ऑफ टियर 3 एंड 4 सिटीज' (The Power of Tier 3 and 4 Cities) को संभव बनाया।

हम शुरुआत टियर III और टियर IV शहरों में रहने और काम करने वाले कई व्यक्तियों को धन्यवाद देकर करना चाहते हैं, जिनकी कहानियाँ और अनुभव इस पुस्तक की आत्मा का निर्माण करते हैं।

अपने परिवारों के प्रति हम एक ऐसा ऋण स्वीकार करते हैं जिसे शब्द शायद ही बयां कर सकें। इस तरह की पुस्तक लिखने के लिए समय, ध्यान और भावनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो अक्सर साझा पलों और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं की कीमत पर आती है। हमारे परिवारों ने न केवल हमारे लंबे समय तक काम करने के घंटों को सहन किया, बल्कि हमें निरंतर बने रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया, जिससे हमें इस प्रयास के पीछे के बड़े उद्देश्य की याद आती रही। उनका धैर्य, विश्वास और प्यार हमारे सबसे मजबूत ताकत के स्रोत बने हुए हैं। हम अपने संपादकीय प्रमुख, सुश्री दिव्या सोनिगरा, प्रकाशकों और समीक्षकों के योगदान को भी स्वीकार करना चाहते हैं, जिन्होंने पांडुलिपि (manuscript) को उसके अंतिम रूप में सावधानीपूर्वक तैयार किया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि और रचनात्मक प्रतिक्रिया ने स्पष्टता, निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित की। उन्होंने हमें याद दिलाया कि विचार न केवल सटीक होने चाहिए बल्कि सुलभ भी होने चाहिए, विशेष रूप से तब जब हमारे पाठक इतने विविध हों।

समान रूप से धन्यवाद के पात्र हमारे साथी, सहयोगी और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट पर चर्चा की, मान्यताओं पर सवाल उठाए और हमें नए स्रोतों की ओर निर्देशित किया। इस प्रक्रिया

के दौरान हमने जिस बौद्धिक साथ का आनंद लिया वह अमूल्य था, जिसने हमें विनम्र और महत्वाकांक्षी दोनों बनाए रखा। अंत में, हम स्वयं 'भारत' को अमूर्त रूप में नहीं, बल्कि उसके जीवंत, सांस लेते रूप में धन्यवाद देना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान हमने जिन कस्बों, बाजारों, स्कूलों, सड़कों और घरों का दौरा किया, उन्होंने हम पर आम भारतीयों के लचीलेपन और रचनात्मकता की छाप छोड़ी। यह उनके सपने और दृढ़ संकल्प ही हैं जो वास्तव में भारत को शक्तिशाली बनाते हैं। यदि यह पुस्तक उनकी इस जीवंतता का एक अंश भी पकड़ने में सफल रही है, तो हम अपने प्रयास को सार्थक मानेंगे।

जैसे ही हम इस कार्य को समाप्त करते हैं, हम इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह पुस्तक भारत के भविष्य के बारे में चल रही बातचीत का एक कदम मात्र है। हमारी आशा है कि पाठकों को इन पृष्ठों के भीतर न केवल जानकारी मिलेगी, बल्कि निवेश करने, नवाचार करने, समावेश करने और सबसे बढ़कर, भारत के छोटे शहरों की असीम क्षमता पर विश्वास करने की प्रेरणा भी मिलेगी। इस मार्ग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हम अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

StrategicBiz.in इज डेडिकेटेड टू एम्पावरिंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, एंड पॉलिसीमेकर्स थ्रू एक्सेसिबल, प्रैक्टिकल, एंड हाई-इम्पैक्ट नॉलेज।

विद अ विजन टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेन्सिव ई-यूनिवर्सिटी, वी प्रोवाइड बुक्स, हैंडबुक्स, आर्टिकल्स, रिसर्च इनसाइट्स, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज डिजाइन्ड टू डेवलप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप कैपेबिलिटीज, एंड बिजनेस एक्सीलेंस।

आवर मल्टीलिंगुअल लर्निंग इकोसिस्टम ब्रिजेस द गैप बिटवीन नॉलेज एंड एक्शन, एनेबलिंग लर्नर्स अक्रॉस डाइवर्स जियोग्राफीज एंड बैकग्राउंड्स टू अक्वायर द स्किल्स एंड इनसाइट्स नीडेड टू ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।

StrategicBiz.in – एम्पावरिंग प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड पॉलिसीमेकर्स.



विषय-सूची

भाग-1

टियर-III एवं टियर-IV शहरों को समझना

अध्याय 1: भारत की जनसांख्यिकी	03
अध्याय 2: कृषि अर्थव्यवस्था के आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होते शहर	10
अध्याय 3: टियर-III एवं टियर-IV शहरों का उभरता हुआ आकांक्षी वर्ग	16
अध्याय 4: आधारभूत संरचना में सुधार	24
अध्याय 5: ग्रामीण भारत के शहरों की लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त	31
अध्याय 6: टियर-III एवं टियर-IV शहरों में दूरसंचार की पहुँच, प्रति व्यक्ति आय तथा डेटा उपयोग में वृद्धि	36

भाग-2

भारत के छोटे एवं मध्यम शहरों की क्षमता का मूल्यांकन

अध्याय 7: बी-श्रेणी के शहरों की औद्योगिक विकास क्षमता	45
अध्याय 8: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का प्रभाव	54
अध्याय 9: भारत के प्रमुख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) केंद्र	61
अध्याय 10: भारत के व्यापारियों एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रों की अंतिम छोर तक पहुँच	69
अध्याय 11: सहकारी समितियों एवं किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की क्रांति	77
अध्याय 12: स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं आंगनवाड़ी की ग्रामीण भारत में बढ़ती शक्ति	81
अध्याय 13: 20-30 वर्ष आयु वर्ग की शैक्षिक क्षमता	88
अध्याय 14: ग्रामीण भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि	96
अध्याय 15: स्थानीय धार्मिक उत्सवों एवं मेलों का बढ़ता प्रभाव, जो पूरे भारत से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं	104
अध्याय 16: प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों एवं मेलों का विकास	115

अध्याय 17:ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म एवं अन्य मीडिया के साथ स्थानीय मीडिया और मनोरंजन का विकास	121
अध्याय 18:ई-कॉमर्स का प्रभाव	126
अध्याय 19:सरकारी नीतियाँ एवं स्मार्ट सिटी की अवधारणा	131

भाग-3

उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में अवसर

अध्याय 20:स्टार्टअप उद्योग का भविष्य	143
अध्याय 21:कृषि एवं संबद्ध उद्योगों में अवसर और विकास	147
अध्याय 22:एफएमसीजी की पहुँच, लॉजिस्टिक्स एवं अंतिम छोर तक संपर्क	156
अध्याय 23:आधारभूत संरचना—सीमेंट, इस्पात, पेंट एवं संबद्ध सेवाएँ	164
अध्याय 24:बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ एवं बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र का तीव्र विकास एवं अपार संभावनाएँ	179
अध्याय 25:ग्रामीण आकांक्षाओं के साथ स्वास्थ्य एवं औषधि उद्योग का विकास	177
अध्याय 26:विलासिता (लक्जरी) सेवाओं का क्षेत्र	187
अध्याय 27:युवाओं में बढ़ती सौंदर्य जागरूकता से उत्पन्न नई माँग	198
अध्याय 28:वस्त्रों की खरीदारी के व्यवहार में परिवर्तन	208
अध्याय 29:ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल चेन का प्रभाव एवं अधिक गहराई तक पहुँचने के अवसर	216
अध्याय 30: ग्रामीण क्षेत्रों में रिटेल चेन का प्रभाव और गहराई तक पैठ बनाने के अवसर	226
अध्याय 31:ग्रामीण कस्बों में ऑटोमोबाइल उद्योग का विस्तार	235
अध्याय 32:नए भारत के लिए नवाचार आधारित लॉजिस्टिक्स एवं वाणिज्यिक वाहन	244
अध्याय 33:सौर ऊर्जा के बढ़ते अवसर	248
अध्याय 34:हाइड्रोजन ऊर्जा की संभावनाएँ	250

भाग-4

भारत के शहरों में डिजिटल उपभोग का स्वरूप

अध्याय 35:ई-भुगतान (डिजिटल भुगतान) का विस्तार	263
अध्याय 36:जीएसटी द्वारा आया परिवर्तन	267
अध्याय 37:भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में यूट्यूब क्रांति	271
अध्याय 38:छोटे शहरों में ई-कॉमर्स की चुनौतियाँ	282
अध्याय 39:ऑनलाइन सेवाएँ एवं सरकार की डिजिटल पहल	289
अध्याय 40: डिजिटल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बुजुर्गों की क्षमता में वृद्धि	298
अध्याय 41:वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल मीडिया एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग हेतु सक्षम बनाना	307

भाग-1

टियर-III एवं टियर-IV शहरों को समझना

भारत की जनसांख्यिकी

परिचय

भारत, जिसकी जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है, अपनी जटिल जनसांख्यिकीय संरचना के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता 7,935 से अधिक नगरों की उपस्थिति है, जिनमें से अधिकांश टियर-3 और टियर-4 श्रेणी में आते हैं। ये छोटे शहरी केंद्र, जो वैश्विक चर्चाओं में प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं, भारत के शहरीकरण के स्वरूप तथा सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की आधारशिला हैं।

ये छोटे नगर, जो बड़े महानगरों की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करते हैं, वास्तव में भारत के शहरी विकास की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इनका स्वरूप विविधतापूर्ण, बहुस्तरीय तथा अपार संभावनाओं से युक्त है। भारत की जनसांख्यिकीय संरचना को समझने के लिए केवल महानगरों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन अपेक्षाकृत छोटे किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण नगरों का विश्लेषण भी आवश्यक है। यह परिचय भारत की जनसांख्यिकीय संरचना तथा उसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की पृष्ठभूमि प्रदान करता है।

छोटे शहरों का देश

भारत को प्रायः “छोटे शहरों का देश” कहा जाता है। यह उपाधि देश के विशिष्ट शहरी वितरण को दर्शाती है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (National Institute of Urban Affairs – NIUA) के अनुसार भारत के शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 63 प्रतिशतका योगदान देते हैं।

विशेष बात यह है कि यह योगदान केवल महानगरों से ही नहीं, बल्कि छोटे नगरों और संक्रमणशील शहरी क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है। ये नगर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, आर्थिक गतिविधियों, श्रमिकों के प्रवासन तथा उपेक्षित क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हैं। ये छोटे शहर अपने स्थानीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण उत्पादकता को व्यापक बाजारों से जोड़ते हैं।

भारत की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है

यद्यपि भारत में शहरीकरण निरंतर बढ़ रहा है, फिर भी अधिकांश भारतीय आज भी बड़े महानगरों के बाहर निवास करते हैं। वर्ष 2022 के अनुसार लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती थी, जबकि लगभग 34 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिन लोगों को “शहरी” श्रेणी में रखा जाता है, उनमें से बड़ी संख्या वास्तव में दस लाख से कम आबादी वाले छोटे नगरों में रहती है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच उन जनगणना नगरों (Census Towns) की संख्या, जिनका स्वरूप तो शहरी था किंतु प्रशासनिक रूप से उन्हें ग्रामीण निकायों द्वारा संचालित किया जाता था, 187 प्रतिशत बढ़ गई। यह परिवर्तन भारत के बदलते बसावट स्वरूप को दर्शाता है तथा शहरी प्रशासन एवं आधारभूत संरचना की योजना के संबंध में नए प्रश्न उत्पन्न करता है।

कार्य परिस्थितियाँ

भारत में कार्य परिस्थितियाँ क्षेत्र, राज्य तथा आर्थिक गतिविधियों के अनुसार अत्यधिक भिन्न-भिन्न हैं। ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें कृषि, लघु उद्योग तथा सड़क किनारे का खुदरा व्यापार प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में नियामकीय निगरानी, सामाजिक सुरक्षा तथा नियमित आय का अभाव रहता है, जिससे श्रमिक अधिकारों एवं आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में कार्य व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक संगठित होने के बावजूद अल्परोजगार (Underemployment) तथा गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy) के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। गिग आधारित रोजगार लचीलापन तो प्रदान करते हैं, किंतु रोजगार सुरक्षा सीमित होती है।

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी नीतियों की माँग करती हैं जो श्रमिक अधिकारों की रक्षा करें, कौशल विकास को बढ़ावा दें तथा व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करें। भारत में

भाग-1 टयिर-III एवं टयिर-IV शहरों को समझना

सामान्यतः प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटेअथवा प्रति सप्ताह 48 घंटेकार्य करने का प्रावधान है, किंतु वास्तविक कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियाँ राज्य एवं उद्योग के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।

भारत की क्रय शक्ति वाली जनसंख्या

भारत की विशाल जनसंख्या एक तेजी से विकसित हो रहे उपभोक्ता वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती है। क्रय शक्ति वाली जनसंख्या अर्थात् वह वर्ग जिसके पास व्यय योग्य आय (Disposable Income) एवं उपभोग की क्षमता है, निरंतर विस्तार कर रहा है। यह वृद्धि केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

इंटरनेट के प्रसार तथा बढ़ती आय के कारण टयिर-2, टयिर-3 और टयिर-4 शहर अब एफएमसीजी (FMCG), इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन तथा ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में माँग के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। उपभोक्ता आधार का यह विविधीकरण समावेशी आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। व्यवसाय भी इस विस्तारित उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों एवं सेवाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे घरेलू माँग और भविष्य की आर्थिक वृद्धि को नई गति मिल रही है।

मार्च 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1.408 अरब है। यह आँकड़ा पिछले दशकों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, जो वर्ष 1951 में लगभग 35.9 करोड़ थी। भारत की जनगणना, जो प्रत्येक दस वर्ष में आयोजित की जाती है, विस्तृत जनसांख्यिकीय जानकारी का प्रमुख स्रोत है।

10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता

भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसमें विशाल युवा आबादी तथा तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग शामिल है, भविष्य के आर्थिक विस्तार के लिए अत्यंत अनुकूल है। 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी अवश्य है, किंतु यदि आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा डिजिटल सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक संरचनात्मक सुधार किए जाएँ तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

छोटे शहरों की क्षमता का पूर्ण उपयोग तथा उन्हें राष्ट्रीय आर्थिक योजना से बेहतर ढंग से जोड़ना इस लक्ष्य की प्राप्ति का निर्णायक कारक सिद्ध हो सकता है। उपयुक्त नीतिगत समर्थन एवं आर्थिक सुधार भारत को इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं।

सुदृढ़ आर्थिक विकास, मजबूत विनिर्माण क्षेत्र तथा “मेक इन इंडिया” जैसी रणनीतिक पहलों के माध्यम से भारत वर्ष 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखता है। इससे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centres – GCCs) से भी लगभग 0.5 ट्रिलियन डॉलर के अतिरिक्त आर्थिक मूल्य सृजित होने की संभावना है। समग्र रूप से भारत के पास 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रबल क्षमता है, किंतु इसके लिए प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा संभावित चुनौतियों का प्रभावी समाधान आवश्यक होगा।

विविध आर्थिक वर्ग : उच्च विकास की अपार संभावनाएँ

भारत की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी सामाजिक एवं आर्थिक विविधता है। निम्न आय वाले ग्रामीण परिवारों से लेकर समृद्ध शहरी वर्ग तक विभिन्न आर्थिक वर्गों का सह-अस्तित्व देश को बहुआयामी तथा बहुस्तरीय आर्थिक संरचना प्रदान करता है।

हालाँकि बड़ी संख्या में श्रमिक आज भी असंगठित परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हाल के आँकड़े श्रम बल की भागीदारी में सुधार तथा बेरोज़गारी में कमी का संकेत देते हैं, किंतु स्थिर वेतन, स्वरोज़गार तथा बिना पारिश्रमिक के पारिवारिक कार्य करने वालों की अधिक संख्या, विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं के बीच, अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है।

भारत में औसतन कार्य अवधि लगभग 47.7 घंटे प्रति सप्ताह है, जिसके कारण कार्य अवधि की दृष्टि से भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ लोग सबसे अधिक समय तक कार्य करते हैं।

कृषि मंडियाँ

कृषि मंडियाँ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। ये व्यापारिक केंद्र लाखों किसानों को उपभोक्ताओं, व्यापारियों तथा प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ते हैं। विशेष रूप से टियर-3 एवं टियर-4 शहरों में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ कृषि आज भी प्रमुख आजीविका का स्रोत है।

हालाँकि लंबे समय से इन मंडियों की कार्यप्रणाली की आलोचना अक्षमताओं, बिचौलियों के शोषण तथा आधुनिक आधारभूत संरचना के अभाव के कारण होती रही है। इन मंडियों में सुधार लाकर अधिक न्यायसंगत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकती है तथा ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

भाग-1 टयिर-III एवं टयिर-IV शहरों को समझना

31 मार्च 2021 तक भारत में 6,920 विनियमित कृषि मंडियाँ (प्रधान मंडियाँ एवं उप-मंडियाँ) कार्यरत थीं। ये मंडियाँ संबंधित राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (APMC) अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित की गई हैं।

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) मंच के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1,400 मंडियों को एकीकृत किया जा चुका है।

यद्यपि भारत में कोई एकल सबसे बड़ी कृषि मंडी नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश को गेहूँ, गन्ना तथा दुग्ध उत्पादन जैसी प्रमुख कृषि उपज के कारण देश का अग्रणी कृषि राज्य माना जाता है। क्षेत्रीय दृष्टि से उत्तर भारत भारतीय कृषि बाजार का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करता है।

भारत की क्रय शक्ति वाली जनसंख्या (जारी)

बढ़ती आकांक्षाओं तथा विकसित हो रहे बाजार तंत्र के कारण भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था निरंतर विस्तृत हो रही है। यह विविधता विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, नवाचारों तथा नीतिगत दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करती है। साथ ही, यह अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला (Resilient) भी बनाती है, क्योंकि जनसंख्या के विभिन्न वर्ग आर्थिक उतार-चढ़ावों पर अलग-अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में संतुलन बना रहता है।

समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से इस विविधता का प्रभावी उपयोग उच्च एवं सतत आर्थिक विकास का आधार बन सकता है। भारत की आर्थिक संरचना विभिन्न आय वर्गों से मिलकर बनी है, जिन्हें व्यापक रूप से निर्धन (Destitutes), आकांक्षी (Aspirers), मध्यम वर्ग (Middle Class) तथा समृद्ध वर्ग (Rich) में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों का निर्धारण मुख्यतः परिवार की वार्षिक आय के आधार पर किया जाता है, जिससे उपभोग के स्वरूप तथा आर्थिक गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

निर्धन (Destitutes)

इस वर्ग में वे परिवार सम्मिलित हैं जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये से कम (वर्ष 2020-21 के अनुसार लगभग 1,700 अमेरिकी डॉलर) होती है। यह वर्ग जीवन स्तर की दृष्टि से सबसे निम्न आर्थिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है।

आकांक्षी वर्ग (Aspirers)

इस वर्ग में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,25,000 रुपये से 5,00,000 रुपये (वर्ष 2020-21 के अनुसार लगभग 1,700 से 6,700 अमेरिकी डॉलर) के बीच होती है। यह वर्ग

आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने तथा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है।

मध्यम वर्ग (Middle Class)

इस वर्ग में वे परिवार शामिल हैं जिनकीवार्षिक आय 5,00,000 रुपये से 30,00,000 रुपये (वर्ष 2020–21 के अनुसार लगभग 6,700 से 40,000 अमेरिकी डॉलर) के बीच होती है। यह वर्ग अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से सुरक्षित माना जाता है तथा आर्थिक जोखिमों के प्रति इसकी संवेदनशीलता कम होती है।

समृद्ध वर्ग (Rich)

इस वर्ग में वे परिवार आते हैं जिनकीवार्षिक आय 30,00,000 रुपये (30 लाख रुपये) से अधिक (वर्ष 2020–21 के अनुसार लगभग 40,000 अमेरिकी डॉलर) होती है। यह वर्ग देश के सबसे संपन्न परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है।

अति समृद्ध वर्ग (Super Rich)

(कुछ अध्ययनों में इसे अलग श्रेणी के रूप में माना जाता है।)

इस वर्ग में वे परिवार शामिल होते हैं जिनकीवार्षिक पारिवारिक आय 2 करोड़ रुपये से अधिक (वर्ष 2020–21 के अनुसार लगभग 2,70,000 अमेरिकी डॉलर) होती है।

वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

वार्षिक पारिवारिक आय

परिवारों को विभिन्न आर्थिक वर्गों में विभाजित करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार उनकीवार्षिक पारिवारिक आय है।

उपभोग के स्वरूप (Consumption Patterns)

वाहन स्वामित्व, वातानुकूलित (एयर कंडीशनर) उपकरणों का उपयोग तथा अन्य उपभोग संबंधी व्यवहार जैसे विशिष्ट उपभोग पैटर्न विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करते हैं।

आर्थिक गतिशीलता (Economic Mobility)

यह वर्गीकरण इस संभावना को भी दर्शाता है कि समय के साथ परिवार अपनी आय में वृद्धि के माध्यम से एक आय वर्ग से दूसरे आय वर्ग में स्थानांतरित हो सकते हैं।

भाग-1 टयिर-III एवं टयिर-IV शहरों को समझना

मध्यम वर्ग का विस्तार (*Growth of the Middle Class*)

अनुमानों के अनुसार 2046-47 तक भारत के मध्यम वर्ग के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही निर्धन तथा आकांक्षी वर्गों की जनसंख्या में क्रमिक कमी आने का अनुमान है।

समृद्ध वर्ग का विस्तार (*Growth of the Rich*)

अनुमान यह भी दर्शाते हैं कि आने वाले वर्षों में समृद्ध वर्ग की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी, जो देश में संपत्ति संचय तथा आय वृद्धि की प्रवृत्ति को इंगित करती है।

आर्थिक संरचना में परिवर्तन (*Shift in Economic Structure*)

निर्धन एवं आकांक्षी वर्गों की हिस्सेदारी में क्रमिक कमी तथा मध्यम एवं समृद्ध वर्गों की बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत देती है कि भारत की आर्थिक संरचना अधिक समृद्ध, उपभोग-प्रधान तथा विकसित अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तित हो रही है।

कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक केंद्रों के रूप में कार्य करते शहर

शक्तिशाली जिला मुख्यालय (The Powerful District Head Quarters)

जिला मुख्यालय भारत के टियर 3 और टियर 4 शहरों के प्रशासनिक और आर्थिक ताने-बाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन के तंत्रिका केंद्रों (nerve centres) के रूप में कार्य करते हुए, वे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से लेकर कानून प्रवर्तन और राजस्व संग्रह तक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का समन्वय करते हैं। अपने नौकरशाही कार्यों से परे, ये शहर प्रभावशाली आर्थिक क्षेत्रों के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। वे प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों, अदालतों, अस्पतालों और जिला-स्तरीय कार्यालयों की मेजबानी करते हैं, जो उन्हें वाणिज्य, शिक्षा और रोजगार के लिए आकर्षण का केंद्र (magnets) बनाते हैं। बेहतर सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, कई जिला मुख्यालयों ने रियल-स्टेट, खुदरा (retail), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। जिला भूगोल के भीतर उनकी केंद्रीयता उन्हें आसपास की अर्ध-शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए हब के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। इस तरह, जिला मुख्यालय संक्रमणकालीन क्षेत्रों (transitional zones) के रूप में कार्य करते हैं जहाँ ग्रामीण भारत शहरी आकांक्षाओं से मिलता है। इसमें उनका बढ़ता महत्व विकेंद्रीकृत शासन और विकास उन्हें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्थानीय उद्यमिता और लक्षित नीति कार्यान्वयन के लिए आदर्श नोड्स (nodes) बनाते हैं।

भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय प्रसार की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, इन 850+ जिला केंद्रों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च, 2025 तक भारत में 780 जिले हैं। ये जिले भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर प्रशासनिक

प्रभाग हैं। वे द्वितीय या तृतीय-स्तरीय प्रशासनिक कोशिकाओं (इकाइयों) के रूप में कार्य करते हैं।

तहसील, ब्लॉक और मंडियाँ (The Tehsils, Blocks and the Mandis)

तहसील और ब्लॉक, जिन्हें पारंपरिक रूप से उप-जिला प्रशासनिक इकाइयों के रूप में देखा जाता है, एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये मध्य-स्तरीय क्षेत्र न केवल प्रशासनिक क्षेत्रों के रूप में बल्कि जमीनी स्तर की आर्थिक गतिविधियों, मुख्य रूप से कृषि, के केंद्र बिंदु (focal point) के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रणाली के केंद्र में मंडियाँ हैं—कृषि बाजार जो आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाते हैं। तहसील और ब्लॉक किसानों को उपभोक्ताओं और बड़े शहरी बाजारों से जोड़कर कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

हाँलाकि, इनमें से कई क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढाँचा अभी भी अविकसित है, जहाँ सीमित डिजिटल पैठ (digital penetration) और लॉजिस्टिक अक्षमताएँ हैं। सड़क कनेक्टिविटी, परिवहन लॉजिस्टिक्स और ई-मंडी जैसे डिजिटल उपकरणों में सुधार करके कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में काफी वृद्धि की जा सकती है। ये स्थान सहकारी समितियों, लघु उद्योगों और सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों का भी समर्थन करते हैं। मंडियाँ, विशेष रूप से टयिर 3 and टयिर 4 शहर, ग्रामीण समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, लेकिन बिचौलियों द्वारा शोषण, खराब भंडारण और मूल्य पारदर्शिता की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इनमें सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीण उत्थान और डिजिटलीकरण के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के साथ, 6000+ तहसीलें और 8000+ ब्लॉक धीरे-धीरे विकास के प्रमुख केंद्रों (hotbeds) में बदल रहे हैं। इन क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाट सकता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सकता है।

क्रय केंद्र और बहुविध आर्थिक गतिविधियाँ (Buying Hubs and Multiple Economical Activities)

टयिर 3 और टयिर 4 शहर तेजी से क्रय केंद्रों (buying hubs) के रूप में विकसित हो रहे हैं—उपभोग के ऐसे केंद्र जो विविधता और मात्रा में अपने महानगरीय समकक्षों को टक्कर देते हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं कई परस्पर जुड़ी गतिविधियों से आकार लेती हैं: खुदरा सेवाएं, कृषि, शिक्षा, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स। इन शहरों ने आकांक्षात्मक उपभोक्तावाद (aspirational consumerism) में एक उछाल देखा है, जिसे बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल जागरूकता और बढ़ती आय से बढ़ावा मिला है। वे लागत लाभ प्रदान करते हैं और भारत के अगले अरब उपभोक्ताओं (next billion consumers) तक पहुँचने के इच्छुक ब्रांडों के लिए टेस्ट मार्केट बन गए हैं।

मंडी व्यापार से लेकर ई-कॉमर्स डिलीवरी तक, ट्यूशन सेंटर्स से लेकर लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग तक विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अभिसरण (convergence) इन शहरों को अत्यधिक गतिशील बनाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी संस्थानों, लघु उद्योगों और बढ़ते वित्तीय क्षेत्र की उपस्थिति एक विविध रोजगार परिदृश्य बनाती है। मौसमी त्यौहार, स्थानीय मेले और साप्ताहिक बाजार भी स्थानीय वाणिज्य में समय-समय पर बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। उनका बहु-क्षेत्रीय चरित्र आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करता है, जिससे किसी एकल उद्योग पर निर्भरता कम होती है। इस विविधता को पहचानकर और बढ़ावा देकर, ये शहर समावेशी आर्थिक विकास और नवाचार के इंजन बन सकते हैं।

भारत में आर्थिक केंद्रों और गतिविधियों की एक विविध और बढ़ती संख्या है। हालांकि विशिष्ट “क्रय केंद्र” (Buying Hubs) औपचारिक रूप से वर्गीकृत श्रेणी नहीं हैं, फिर भी प्रमुख शहर और क्षेत्र विनिर्माण, सेवाओं और व्यापार सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए केंद्रीय बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। ये केंद्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुसार, भारत में शहर केवल 3% भूमि पर बसे हैं, लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में 60% का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में शहर देश की मात्र 3.0% भूमि पर कब्जा करते हैं, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनका योगदान भारी-भरकम 60.0% (पाद टिप्पणी 1) है। इसी तरह, अनुमानित जिला GDP4 का विश्लेषण दर्शाता है कि किसी जिले की शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी में प्रत्येक प्रतिशत अंक की वृद्धि, जिला GDP में 2.7% की वृद्धि से जुड़ी है।

मंडियों के व्यापारी (Traders of Mandis)

कृषि मंडियों के व्यापारी भारत की कृषि-आपूर्ति श्रृंखला (Agri-supply chain) में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं, विशेष रूप से टियर 3 और टियर 4 शहरों में। वे किसानों से बड़े बाजारों या प्रसंस्करणकर्ताओं (processors) तक उपज की आवाजाही को सुगम बनाते हैं, जो अक्सर विश्वास, बातचीत और अनौपचारिक अनुबंधों की एक पारंपरिक लेकिन जटिल प्रणाली के भीतर काम करते हैं। ये व्यापारी, जो आमतौर पर स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित होते हैं, कृषि चक्र, बाजार के रुझान और क्षेत्रीय मूल्य निर्धारण का गहरा ज्ञान रखते हैं।

हालांकि, बिचौलियों की व्यापकता के कारण अक्सर उनकी भूमिका की आलोचना की जाती है, जो किसानों के लाभ मार्जिन को कम करते हैं। जहाँ कुछ व्यापारी वास्तव में छोटे किसानों के लिए तरलता (liquidity) और बाजार तक पहुँच को सक्षम बनाते हैं, वहीं अन्य प्रणालीगत खामियों का फायदा उठाते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, मंडी व्यापारी आर्थिक रूप से प्रभावशाली बने हुए हैं। उनकी वित्तीय पहुँच, स्थानीय नेटवर्क और जोखिम उठाने की क्षमता उन्हें इन परिस्थितिकी

भाग-1 टयिर-III एवं टयिर-IV शहरों को समझना

तंत्रों में अनौपचारिक फाइनेंसों, वितरकों और यहाँ तक कि नियोक्ताओं के रूप में स्थापित करती है।

मंडियों के डिजिटलीकरण और सुधार के हालिया प्रयास मूल्य निर्धारण और व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिचौलियों के हटने (disintermediation) के डर से कई व्यापारी बदलाव का विरोध कर रहे हैं। आधुनिक वित्तीय साधनों, डिजिटल साक्षरता और विनियमन के माध्यम से व्यापारियों को सशक्त करना उनकी भूमिका को औपचारिक रूप देने और उन्हें भारत के व्यापक आर्थिक विकास में एकीकृत करने में मदद कर सकता है। उनके योगदान को पहचानना और उनके संचालन का आधुनिकीकरण करना अधिक कुशल, निष्पक्ष और लचीले ग्रामीण बाजारों के निर्माण की कुंजी होगी। 11 फरवरी, 2024 तक ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म पर 2.53 लाख से अधिक व्यापारी पंजीकृत थे। ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है जो पूरे भारत में कृषि उपज विपणन समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है। 11 फरवरी 2024 तक, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया था।

शैक्षणिक केंद्र और आकांक्षा निर्माण (Educational Hubs and Aspiration building)

कई टयिर 3 और टयिर 4 शहर शैक्षणिक केंद्रों (educational hubs) के रूप में उभरे हैं, जो आसपास के गांवों के स्थानीय और प्रवासी दोनों छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये शहर कोचिंग सेंटers, निजी स्कूलों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों की बढ़ती संख्या का घर हैं। जीवन स्तर को ऊपर उठाने (upward mobility) की इच्छा प्रतिस्पर्धी शिक्षा की संस्कृति को संचालित करती है, जहाँ परिवार स्कूली शिक्षा और कोचिंग में महत्वपूर्ण निवेश करते हैं, जो अक्सर व्यक्तिगत वित्तीय तनाव के बावजूद होता है। कई लोगों के लिए, शिक्षा गरीबी या ग्रामीण निर्भरता से बाहर निकलने की प्राथमिक सीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। परिणामस्वरूप, ये शहर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को पास करने, कौशल हासिल करने या सरकारी या निजी नौकरियों में प्रवेश करने के इच्छुक युवाओं की निरंतर आमद (आगमन) का गवाह बनते हैं।

यह शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र ट्यूटर्स, प्रशासकों, हॉस्टल मालिकों और किताबों की दुकानों के लिए रोजगार भी पैदा करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, बुनियादी ढाँचे की कमियाँ, सीमित शिक्षण संसाधन और सामर्थ्य (affordability) की चुनौतियाँ अभी भी गंभीर समस्याएँ बनी हुई हैं। गुणवत्तापूर्ण संकाय (faculty), डिजिटल कक्षाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण में निवेश परिणामों को बेहतर बना सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार, निजी संस्थानों और स्थानीय उद्यमियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने से एक अधिक समावेशी और प्रतिक्रियाशील शिक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है। ये शैक्षणिक शहर न केवल शिक्षा प्रदान

करते हैं बल्कि आकांक्षाओं का भी पोषण करते हैं—एक अमूर्त लेकिन शक्तिशाली शक्ति है जो भारत के भविष्य के जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को आकार दे रही है।

AISHE 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में 1,168 विश्वविद्यालय और 42,825 कॉलेज शामिल हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की संख्या 2014-15 में 51,534 से 13.8% बढ़कर 2022-23 में 58,643 हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में 12,002 स्टैंड अलोन (स्वतंत्र) संस्थान हैं। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद सहित कई शहरों को शैक्षणिक केंद्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सूक्ष्म से मध्यम उद्यमी (Micro to medium entrepreneurs)

टियर III और IV शहर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए उपजाऊ जमीन हैं, जो भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। छोटे पैमाने के विनिर्माण से लेकर सिलाई इकाइयों तक, खाद्य प्रसंस्करण से लेकर स्थानीय हस्तशिल्प तक, इन शहरों के उद्यमी उल्लेखनीय नवाचार और अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। महानगरीय शहरों की तुलना में कम नियामक बाधाओं (regulatory hurdles) और कम परिचालन लागत के साथ, ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से मोबाइल-आधारित भुगतान और ई-कॉमर्स ने इन व्यवसायों के लिए बाजार तक पहुँच का विस्तार किया है। स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त योजनाओं के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम भी गति पकड़ रहे हैं।

उनके योगदान के बावजूद, ये उद्यमी अक्सर औपचारिक ऋण पहुँच, कुशल जनशक्ति, विपणन और प्रौद्योगिकी अपनाने से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं। मुद्रा ऋण, स्टार्टअप इनक्यूबेटर और स्थानीय परामर्श कार्यक्रमों जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सहायता प्रणालियों को मजबूत करना उनकी स्थिरता और मापनीयता (scalability) को बढ़ावा दे सकता है। इस खंड में औपचारिकीकरण और नवाचार को प्रोत्साहित करना न केवल रोजगार सृजन के लिए बल्कि भारत के आर्थिक रोडमैप में परिकल्पित समावेशी और विकेंद्रीकृत विकास मॉडल को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भंडारण (Warehousing)

टियर III और IV शहरों में भंडारण बुनियादी ढांचा तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहा है, विशेष रूप से कृषि-लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स गतिविधियों में उछाल के साथ। ये शहर कम भूमि लागत, ग्रामीण उत्पादन केंद्रों से निकटता और बढ़ती उपभोग मांग के कारण गोदाम (warehouses) स्थापित करने के लिए आदर्श स्थानों के रूप में कार्य करते हैं। भंडारण व्यवस्था भंडारण, सूची प्रबंधन (inventory management) और समय पर वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित करता है,

भाग-1 टयिर-III एवं टयिर-IV शहरों को समझना

जिससे यह आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) का एक प्रमुख घटक बन जाता है। कृषि-भंडारण (Agri-warehousing) किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए लाभ (leverage) प्रदान करता है। साथ ही, ई-कॉमर्स कंपनियां तेजी से अंतिम मील तक डिलीवरी (last-mile delivery) सुनिश्चित करने के लिए छोटे शहरों में पूर्ति केंद्र (fulfilment centres) स्थापित कर रही हैं।

हालांकि, अधिकांश गोदाम अभी भी बुनियादी बुनियादी ढाँचे और मैनुअल प्रक्रियाओं के साथ काम करते हैं। यंत्रीकरण (mechanisation), कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत से दक्षता और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार हो सकता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और लॉजिस्टिक्स पार्कों में निवेश भी इन केंद्रों को क्षेत्रीय वितरण हब में बदल सकता है। भंडारण न केवल व्यापार और खुदरा क्षेत्र का समर्थन करता है बल्कि ड्राइवरों, लोडरों, इन्वेंट्री प्रबंधकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए रोजगार भी पैदा करता है। जैसे-जैसे आपूर्ति श्रृंखलाएं विकेंद्रीकृत होंगी और ग्रामीण मांग बढ़ेगी, गैर-महानगरीय क्षेत्रों में भंडारण की भूमिका और भी रणनीतिक हो जाएगी, जिससे भारत के विशाल भौगोलिक विस्तार में सुचारू आर्थिक प्रवाह सक्षम होगा।

भारत का भंडारण क्षेत्र मजबूत वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जेएलएल (JLL) के अनुसार, शीर्ष आठ शहरों में ग्रेड ए और बी भंडारण स्थान का कुल स्टॉक 2023 के अंत में 371 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया है। यह 15% वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) वृद्धि को दर्शाता है। इन्वेस्ट इंडिया (Invest India) के अनुसार, 2022 से 15.64% की सीएजीआर (CAGR) के साथ बाजार के 2027 तक 34.99 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के टयिर 2 और 3 शहर ई-कॉमर्स विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कारकों से प्रेरित होकर भंडारण विकास में उछाल का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि खोज परिणामों में टयिर 3 और 4 शहरों के लिए विशिष्ट संख्याएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, डेटा से पता चलता है कि ये क्षेत्र समग्र भंडारण स्टॉक में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, अकेले उभरते टयिर II-III शहरों में लगभग 100 मिलियन वर्ग फुट हिस्सा है, जो कुल स्टॉक का लगभग 18.7% प्रतिनिधित्व करता है।



कुनाल अवस्थी इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के स्नातक हैं तथा उन्हें भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्योगों में 26 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। उन्हें एफएमसीजी (FMCG) क्षेत्र और ग्रामीण बाजारों का गहन ज्ञान है। उन्होंने टिकाऊ रिटेल मॉडल विकसित करने, उपभोक्ता ब्रांडों की वृद्धि को गति देने तथा शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली अभिनव वितरण रणनीतियाँ तैयार करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

वर्तमान में वे भारत के अग्रणी एफएमसीजी ब्रांड हमदर्द फूड्स में कंसल्टेंट – स्ट्रैटेजिक बिजनेस एवं ई-कॉमर्स के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही वे पॉलीनेशियन किंगडम ऑफ अटूर्ई/किंगडम ऑफ हवाई के ग्लोबल ट्रेड कौंसल भी हैं। इसके अतिरिक्त वे गंगाराम कोलमेट हॉस्पिटल के निदेशक तथा एशियन सीनियर्स टूर एवं एशियन सीनियर्स पीजीए गोल्फ के लिए भारत के राजदूत (Indian Ambassador) के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ-साथ वे एक सफल क्रमिक उद्यमी (Serial Entrepreneur) के रूप में खनन, कमोडिटी ट्रेडिंग, सीमा-पार व्यापार (Cross-border Trade) तथा बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े अनेक उपक्रमों का सफल संचालन भी कर रहे हैं।



सरबजीत सिंह पुरी फतेह रूरल लिमिटेड के संस्थापक एवं चेयरमैन हैं। वर्ष 2003 में स्थापित फतेह रूरल, मुंबई मुख्यालय वाली भारत की अग्रणी ग्रामीण विपणन एवं विज्ञापन (Rural Marketing & Advertising) एजेंसियों में से एक है, जिसके देशभर में 12 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं।

अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने हजारों ग्रामीण विपणन अभियानों का सफल नेतृत्व किया है तथा 100 से अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ कार्य किया है। उनके प्रमुख ग्राहकों में Bayer, Syngenta, L&T, Godrej, Ecozen, Reliance, Tata, Mahindra, Sonalika Tractors, Hamdard, HDFC सहित अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ शामिल हैं।

उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में पाँच लाख किलोमीटर से अधिक की यात्राएँ की हैं और किसानों, ग्रामीण समुदायों, वितरकों तथा खुदरा विक्रेताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित किया है। इन अनुभवों ने उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धतियों, फसलों, तकनीक अपनाने की प्रवृत्ति, उत्पाद उपयोग, आय स्तर तथा ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया है।

उनका व्यक्तिगत उद्देश्य आधुनिक तकनीक को पारंपरिक विज्ञापन एवं संचार माध्यमों के साथ जोड़कर जमीनी वास्तविकताओं और आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोण के बीच प्रभावी सेतु का निर्माण करना है।

भविष्य की आकांक्षाएँ

- एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में संगठन का विस्तार करना।
- न्यूयॉर्क (अमेरिका) में वैश्विक मुख्यालय (World Headquarters) की स्थापना करना।
- फतेह रूरल के विस्तार हेतु निवेश एवं वित्तपोषण (Funding) के नए अवसरों की तलाश करना।



₹ 599/-

natrajpublishing@gmail.com